

**भारत सरकार**  
**जल शक्ति मंत्रालय**  
**जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग**  
**लोक सभा**  
**अतारांकित प्रश्न संख्या 1677**  
**जिसका उत्तर 05 दिसम्बर, 2024 को दिया जाना है।**

.....

**पीएमकेएसवाई के तहत बिष्णुपुर, पश्चिम बंगाल में सिंचाई परियोजनाएं**

**1677. श्री सौमित्र खान:**

क्या जल शक्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) पिछले पांच वर्षों और चालू वर्ष के दौरान पश्चिम बंगाल के बिष्णुपुर लोक सभा निर्वाचन क्षेत्र में प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना (पीएमकेएसवाई) के अंतर्गत सिंचाई परियोजनाओं के लिए आवंटित और वितरित धनराशि का ब्यौरा क्या है;
- (ख) उक्त अवधि के दौरान पश्चिम बंगाल में पीएमकेएसवाई के अंतर्गत सिंचाई अवसंरचना विकास परियोजनाओं के लिए उपयोग की गई धनराशि का ब्यौरा क्या है तथा उनकी चालू/पूर्ण/विलंबित स्थिति का ब्यौरा क्या है;
- (ग) क्या बिष्णुपुर लोक सभा निर्वाचन क्षेत्र में पीएमकेएसवाई के अंतर्गत सिंचाई परियोजनाओं के संबंध में कोई प्रस्ताव लंबित हैं और यदि हां, तो उनके लंबित रहने के क्या कारण हैं; और
- (घ) क्या बिष्णुपुर लोक सभा निर्वाचन क्षेत्र में पीएमकेएसवाई पहलों के कार्यान्वयन में किन्हीं चुनौतियों और देरी का सामना करना पड़ा है और यदि हां, तो इन चुनौतियों के कारणों सहित तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

**उत्तर**

**जल शक्ति राज्य मंत्री**

**श्री राज भूषण चौधरी**

**(क):** प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना (पीएमकेएसवाई) खेतों में जल की वास्तविक पहुंच बढ़ाने और सुनिश्चित सिंचाई के अंतर्गत खेती योग्य भूमि को विस्तारित करने, खेतों में जल उपयोग दक्षता को सुधारने और सतत जल संरक्षण प्रथाएं शुरू करने के लक्ष्य के साथ वर्ष 2015-16 के दौरान आरंभ की गयी थी।

प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना एक अम्ब्रेला योजना है, जिसमें दो प्रमुख घटक हैं, जो इस मंत्रालय द्वारा कार्यान्वित की जा रही हैं अर्थात् त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम (एआईबीपी) और हर खेत को पानी (एचकेकेपी)। जबकि हर खेत को पानी में चार उप-घटक अर्थात् कमान क्षेत्र विकास और जल प्रबंधन,

सतही सूक्ष्म सिंचाई, जल निकायों की मरम्मत, नवीनीकरण और पुनरुद्धार एवं भूजल विकास घटक शामिल है। फिर भी, हर खेत को पानी के उप-घटक कमान क्षेत्र विकास और जल प्रबंधन का कार्य त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम के पारी पासू कार्यान्वित किया जा रहा है।

इसके अलावा, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना में भी दो घटक शामिल हैं, जिन्हें दूसरे मंत्रालयों द्वारा कार्यान्वित किया जा रहा है। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना का वाटरशेड विकास घटक भूमि संसाधन विभाग द्वारा कार्यान्वित किया जा रहा है। कृषि किसान कल्याण विभाग द्वारा कार्यान्वित प्रति बूंद अधिक फसल घटक को प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के भाग के रूप में दिसंबर, 2021 तक कार्यान्वित किया गया था।

देश में वृहद, मध्यम और सूक्ष्म सिंचाई परियोजनाओं के माध्यम से सिंचाई अवसंरचना विकसीत की जाती हैं और ये परियोजनाएं प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना में, त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम, सतही सूक्ष्म सिंचाई और मरम्मत, नवीनीकरण और पुनरुद्धार घटक के अंतर्गत शामिल है। इस समय, इन घटकों के अंतर्गत पश्चिम बंगाल की कोई परियोजना नहीं है, फिर भी प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के अन्य घटकों अर्थात् पीडीएमसी और डब्ल्यूडीसी के माध्यम से राज्यों को निधि प्रदान की जा रही है, जो मुख्य रूप से क्रमशः सूक्ष्म सिंचाई और वाटरशेड विकास पर केंद्रीत है। विष्णुपुर लोक सभा निर्वाचन क्षेत्र, पश्चिम बंगाल में, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम-कमान क्षेत्र विकास एवं जल प्रबंधन, सतही सूक्ष्म सिंचाई और मरम्मत, नवीनीकरण और पुनरुद्धार एवं भूजल घटक के लिए पिछले पांच वर्षों और इस वर्ष कोई निधि जारी नहीं की गई है। पीएमकेएसवाई-पीडीएमसी घटक के अंतर्गत 84.43 लाख रुपये आबंटित और संवितरित किए गए हैं। पीएमकेएसवाई-डब्ल्यूडीसी घटक के अंतर्गत 48.384 करोड़ रुपये का केंद्रीय हिस्सा जारी किया गया है।

**(ख):** पश्चिम बंगाल में, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम-कमान क्षेत्र विकास एवं जल प्रबंधन, सतही सूक्ष्म सिंचाई और मरम्मत नवीनीकरण और पुनरुद्धार एवं भूजल घटक के लिए पिछले पांच वर्षों में कोई निधि जारी और उपयोग नहीं की गई है। पीएमकेएसवाई-पीडीएमसी घटक के अंतर्गत 78.5382 करोड़ रुपये का उपयोग किया गया है। पीएमकेएसवाई-डब्ल्यूडीसी घटक के अंतर्गत 377.39 करोड़ रुपये सहित राज्य के हिस्से की धनराशि और प्राप्त अन्य राशि का उपयोग किया गया है।

**(ग) और (घ):** विष्णुपुर लोक सभा निर्वाचन क्षेत्र में प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के अंतर्गत सिंचाई परियोजनाओं के संबंध में कोई प्रस्ताव लंबित नहीं है। विष्णुपुर लोक सभा निर्वाचन क्षेत्र में प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना पहल के कार्यान्वयन में कोई चुनौती या विलंब की सूचना प्राप्त नहीं हुई है।